स्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया की 25 वर्षों की यात्रा ; भारत के अगले बुनियादी ढांचा विकास के चरण पर चर्चा

मुंबई, कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रजत जयंती वर्ष मनाया। इस अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएफआई ने पिछले 25 वर्षों के दौरान नीति, कामकाज और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों की इस अवसर पर समीक्षा की। '25 वर्षों की निर्माण उत्कृष्टता और भविष्य की ओर आगे बढ़ने' की थीम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में [illegible] के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, [illegible] मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत के अगले बुनियादी ढांचा विकास के चरण पर चर्चा की।कार्यक्रम के दौरान तकनीक, मशीनीकरण, परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन, प्रशासन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर चर्चा की गई। निर्माण, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण क्षेत्र में अधिक कार्यक्षमता, उत्पादकता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।सीएफआई के रजत जयंती समारोह में [illegible] के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, [illegible] ने कहा, 'भारत के निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पिछले 25 वर्षों में योगदान देने के लिए मैं सीएफआई को बधाई देता हूं। 'मुंबई को नए सिरे से सक्षम बनाना, [illegible] को नया स्वरूप देना और पूरे क्षेत्र को अधिक कनेक्टेड एवं आसानी से पहुंच योग्य बनाना, साथ ही नए स्थान और अवसर उपलब्ध कराना' हमारा लक्ष्य है। 'आने वाले समय में बुनियादी ढांचे के विकास का एक बड़ा चरण हमारे सामने है। ऐसे में सभी के लिए पर्याप्त काम उपलब्ध होगा। हालांकि, इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिक क्षमता, कौशल और संसाधनों की आवश्यकता होगी। भारतीय ठेकेदारों ने मेट्रो, कोस्टल रोड और अटल सेतु जैसी बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके अपनी क्षमता पहले ही साबित की है। इनमें से कई परियोजनाओं को उन्होंने पहली बार क्रियान्वित किया है। 'उन्होंने आगे कहा, 'आज एकीकृत बुनियादी ढांचे और तकनीक की मदद से मुंबई में यात्रा को अधिक आसान और सुगम बनाना हमारा लक्ष्य है। भविष्य में मुंबई में यात्रा करने के लिए किसी यात्री के पास सिर्फ एक चार्ज किया हुआ मोबाइल फोन होना ही पर्याप्त हो, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा है। विकास की इस गति को आगे बढ़ाने और अगले 25 वर्षों के बुनियादी ढांचे के विकास को दिशा देने के लिए सीएफआई उद्योग जगत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 'इस अवसर पर सीएफआई के अध्यक्ष और [illegible] के [illegible] के सलाहकार श्री एम. वी. सतीश ने कहा, 'पिछले 25 वर्षों से सीएफआई ने उद्योग जगत की चुनौतियों की पहचान करने, संवाद को बढ़ावा देने और निर्माण एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए अधिक सक्षम वातावरण तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उद्योग जगत के प्रमुख लोगों की उपस्थिति और समर्थन इस क्षेत्र के विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उद्योग को एकजुट करने और उसके विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाली इस यात्रा पर हमें गर्व है। 'उन्होंने आगे कहा, 'भारत बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में अब परियोजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने, तकनीक और मशीनीकरण को अपनाने, सुरक्षा और टिकाऊपन को प्राथमिकता देने तथा नीतिगत और कार्यप्रणाली से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना आवश्यक है। अगले 25 वर्षों के लिए अधिक आधुनिक, सक्षम, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता है। सीएफआई इस यात्रा को दिशा देने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। 'सीएफआई के रजत जयंती कार्यक्रम में सीएफआई के पदाधिकारी, संस्थापक सदस्य और पूर्व पदाधिकारी, विशेषज्ञ पैनल के सदस्य, कार्यकारी समिति के सदस्य और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पश्चाताप...

बहुत पुरानी बात है। शिव अपने बड़े भाई से मनमुटाव के कारण अपना घर-बार छोड़कर दूसरे राज्य में आ बसा था। साथ में पत्नी उषा और एक छोटा सा बेटा प्रमोद। नए राज्य में जीवन आसान नहीं था। सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा। शिव दिन में मजदूरी करता, मुंशीगिरी करता, रात में लोगों के घरों में काम करता और कभी-कभी दूसरों के खेतों में घास भी काटता। शरीर थक जाता पर हौसला नहीं टूटता। उसकी एक ही इच्छा थी - मेरा बेटा प्रमोद पढ़-लिख कर हमारा सहारा बनेगा।प्रमोद धीरे-धीरे बड़ा हुआ। पिता ने अपनी सारी इच्छाएं मारकर, फटे जूते-पुराने कपड़ों में गुजारा करके उसे पढ़ाया। जब प्रमोद को बड़े शहर के कॉलेज में जाना पड़ा, तो शिव ने कर्ज लेकर उसका दाखिला कराया। उसे लगा, कुछ दिन की तकलीफ है, फिर बेटा संभाल लेगा। पर शहर की चकाचौंध ने प्रमोद को बदल दिया। नए दोस्त, नए शौक, दिखावे की जिंदगी। उसका खर्च बढ़ता गया और वह हर महीने पिता से झूठ बोलकर पैसे मंगवाता रहा। उधर शिव पर कर्ज बढ़ता गया। उम्र ढल रही थी, शरीर जवाब दे रहा था, पर वह बेटे की हर मांग पूरी करने के लिए और कर्ज लेता रहा। प्रमोद भूल चुका था कि वह पैसा कहाँ से आ रहा है। वह पढ़ाई से दूर, ऐशो-आराम में डूब गया। एक दिन जब प्रमोद ने फिर पैसों के लिए फोन किया, घर में एक रुपया भी नहीं था। कर्ज देने वालों ने भी मना कर दिया था। तब उषा ने धीरे से अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और बोली - इसे बेच दो। यह देखकर शिव फूट-फूट कर रो पड़ा, बोला - 'यह तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है, इसे बेच दिया तो मेरे जीवन को धिक्कार है।' मेहनत रंग लाई उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसने उसी चौकीदारी की चौकी पर बैठकर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। दिन में घर पर पढ़ता, रात में लालटेन की रोशनी में ड्यूटी पर पढ़ता, पहले ही प्रयास में वह सफल हुआ, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया।उसने माता-पिता को कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि कंपनी की ट्रेनिंग के लिए मैसूर जा रहा हूँ। ट्रेनिंग पूरी कर जब वह पहली बार सरकारी गाड़ी, सुविधाओं के साथ अपने पुराने किराए के घर पहुँचा, तो शिव और उषा की आँखों से खुशी के आँसू बह निकले। प्रमोद उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उसी के हाथों से पिता के सारे कर्ज चुकाए। जिन कर्जदारों ने उसके माता-पिता को गालियाँ दी थीं, उन्हें भी सम्मान के साथ पैसे लौटाए। आज प्रमोद कलेक्टर है। उसके माता-पिता अब किराए के मकान में नहीं, सरकारी आवास में सम्मान के साथ रहते हैं। एक पश्चाताप ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी।

प्रमोद कुमार चौहान कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश

खेती किसानी...! किस.. किसको... कैसे बताएं अपनी कहानी ...

किसान पुत्र अपने जन्म से ही खुले आसमान में पारंपरिक अस्थाई पालने (तिपाई)में पलता बढ़ता है । तेज धूप हवा बारिश के थपेड़ों को झेलता है। थोड़ा बड़ा होने पर धरती माँ की विशाल गोद पाता है। जैसे-जैसे समझ विकसित होती है अपनी नजर के सामने माता-पिता व परिजनों को धरती माँ की गोद में हाड़ - तोड़ मेहनत करते देखता है। वही जज्बा , संस्कार , संस्कृति उसके विचारों में गहराई से उतरती जाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले , उगले हीरे मोती ... जैसे गीत और पुरखों की पारंपरिक खेती के तौर तरीकों से उत्साहित वह अपने देश के लिए खाद्यान्न , फलोद्यान , औषध उत्पादन में जीवन जुटा देता है। युवा होते-होते उस किसान का जोश कापूर होने लगता है , जब वह कृषि आर्थिकी की आय-व्यय सारणी पर गौर करता है।

आज के दौर में सबसे पहले वह अपनी खेती को लुट खसोट, दबंगई व अवसरवादियों से बचाने के प्रबंधन पर खर्च करता है फिर उसकी हकाई जुताई , बोनी की तैयारी । पशुओं के गोबर की जीवाश्म युक्त खाद की व्यवस्था। लागत कम करने के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों को बनाने का अग्रीम प्रबंधन। फिर बीज की छनाई-बिनाई , बीज परीक्षण, बीज उपचार सामग्री क्रय करना। बोनी के लिए उचित संसाधन जुटाने , उन्हें चाक चोबंद करना । तब तक वैशाख , ज्येष्ठ माह की तपन पाकर धरती माँ संपूर्ण ऊर्जा समेटे , बीज को अंकुरित करने को तत्पर हो उठती है।

इस वर्ष खरीफ सीजन की ही बात करें तो बारिश सघन नहीं रही। प्री मानसूनी बरसात , फिर मानसूनी बारिश भी खंड वर्षा के रूप में हुई। बरसात की आस लिए किसान कब तक बैठा रहता। खेतों में नमी को देख बुवाई कर दी। प्रभु कृपा से अंकुरण भी अच्छा हुआ । फसल बढ़वार की गति भी अच्छी देखी गई। तदनुरूप उम्मीद में किसान कृषि क्रियाएं करता रहा। वहीं कम नमी वाले क्षेत्रों में दोबारा और कहीं-कहीं तिबारा बोनी की स्थिति भी बनी। किसान का खर्चे पर खर्च। वरिष्ठ किसानों की माने तो सबसे अच्छी बारिश के महीने आषाढ़ , सावन व भाद्रपद में जहां तेज बारिश होती है इस दफा अधिकांशतः फुहारे ही बरसी । जिससे कुंए , बावड़ी , तालाब रिते रह गए। यही नहीं फसलों को स्वस्थ रखने में किसानों ने तीन-तीन बार सुरक्षात्मक कीटनाशक दवाओं के स्प्रे भी किये। फूल-फल आने के समय बारिश की बेरुखी ने किसानों की सांसें ऊपर नीचे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । उपर से पीले मोजेक से खेत पीले हो गए । तापमान बढ़ने का दौर ऐसे चला कि नमी के अभाव में फसलें लटक गई । दीपावली के आसपास आने वाली फसलें यकायक सितंबर के अंतिम व अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही आ गई । उत्पादन तो प्रभावित हुआ ही । खेत खाली होने पर उच्च तापमान से रही सही नमीं सतत कम होती जा रही है। फसल बोने का उचित समय नहीं (सरसों व चना को छोड़कर) होने से बोनी भी नहीं हो पा रही है। जल स्रोत खाली होने से रबी सीजन बुरी तरह से प्रभावित होने की ओर इंगित करता लग रहा है। गेहूं , सब्जियां , औषधिय फसलों का क्षेत्राच्छादन , नदियों व तराई क्षेत्र या जहां अंतिम बारिश हुई हो वहाँ यथासमय गेहूं लगने की संभावना कहीं जा सकती है। शेष क्षेत्र या तो कोरे रह सकते हैं या बो देने पर भगवान भरोसे (मावठा होने पर) उत्पादन मिलने की संभावनाएं बनेंगी।

क्षेत्रवार किसानों में जोरों से चर्चा है कि सिंचाई के लिए निर्मित बांधो , तालाबों का पानी उद्यमों को दिए जाने से उनके खलिहान व अनाज भंडारण रिते रहेंगे। वे आश्चर्यचकित हैं की जल स्रोतों में जिन क्षेत्रों का पानी बहकर आ रहा है उन क्षेत्र वासियों की वर्षो से पीने व उद्वहन सिंचाई के लिए , बार-बार मांग के बाद भी पानी नहीं मिलना वहीं स्थापित उद्योगों का चंद दिनों में पानी की अनुमति दे देना समझ से परे है।

विचारणीय पक्ष यह भी है कि उत्पादन कम होने के बाद भी उनकी फसलों के मूल्य , लागत अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। गन्ना , मक्का , चांवल , प्याज जैसी जन उपयोगी फसलों का अन्य उत्पाद बनाने में उपयोग होने लगा है निश्चित ही अच्छी बात है , लेकिन उपभोक्ताओं में उनकी कमी की पूर्ति हेतु प्रभावित फसलों का क्षेत्राच्छादन व उत्पादन बढ़ाने व उनके लिए लाभदायक मूल्य की नीति दृष्टव्य नहीं है ।

अल नीनो के प्रभाव से मौसमी असंतुलन की स्थिति से खेती किसानी पर हो रहे प्रभाव पर कोई नहीं बोलता है। कश्मीर जैसे ठंडे इलाके में तापमान की बढ़ोतरी से केसर जैसी बहु उपयोगी फसल उत्पादन कम होने व उसके कंद सूखने के समाचार है। निमाड़ , झाबुआ , रतलाम में कपास फसल क्षेत्र कम होने की जानकारी आ रही है ? पीला सोना के रूप में ख्यात तिलहनी फसल सोयाबीन का मध्य प्रदेश में रकबा कम होना भी सुर्खियों में है! कभी-कभी प्याज टमाटर के बढ़ते दामों से किसानों को लाभ मिलने की स्थिति बनने पर शासन प्रशासन स्तर पर असजता क्यों लगने लगती है? इन तमाम बिंदुओं पर जिला स्तर पर समीक्षा कर क्षेत्राच्छादन व उत्पादन पर संतुलन नहीं बन सकता ?

हमारी कृषि अब मात्र अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रही वजह बिल्कुल स्पष्ट है पहले हमारी खेती पशुओं , प्राकृतिक साधनों व कृषि श्रम पर आश्रित रही थी । पशुओं से दूध और जीवाश्म युक्त खाद मिलना सुनिश्चित होता था। उपलब्ध लकड़ी के कृषि औजार या तो वै खुद निर्माण कर लेते थे या केवल श्रम लागत में बन जाते थे। यानी खेती में लागत व्यय कम होकर जो भी फसल/अन्न मिलता था , वह स्वयं के अधिकतम श्रम का फल होता था। आज मशीनीकरण में मशीन क्रय करने का भारी खर्च उसको चलायमान बनाए रखने के लिए ईंधन व्यय , रखरखाव का खर्च । टूट फुट में नए सामान का व्यय के बीच उसके महंगें भाव के आवश्यक टायर , बेट्री तो निश्चित ही बजट बिगाड़ने वाली सामग्री लगती है ! सबसे बड़ी बात मशीनरी साधनों के खर्च के साथ-साथ किसान की उन पर निर्भरता भी बढ़ गई। ट्रैक्टर के साथ किस-किस तरह के कितने साधन खरीदें ! प्लाऊ , टीलर, कल्टीवेटर , हैरो, रोटावेटर , सीड ड्रिल , थ्रेसर , हार्वेस्टर , रिपर , पावर स्प्रेयर जैसी कई आधुनिक मशीनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ गई । कम जोत वाले किसान के लिए तो यह खर्च बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए कंटीले तार या झाली का खर्च। इसको भी तोड़कर अंदर घुस जाने वाले पशुओं के लिए झटका मशीन पर व्यय। कुंए से पानी की मोटर , केबल चोरी का असामयिक व्यय। इस तरह सुविधाओं के लिए अंतहीन भारी खर्च। यह सारे खर्चे उसे फसल आने के पूर्व करना होते हैं। इतना ही नहीं बात यही नहीं रुकती है उनकी फसल का भाव खरीददार तय करता है जिसे यह नहीं मालूम की कितनी लागत लगाकर किसान उस फसल को यहाँ तक लाया है। जो भाव बोला गया उस पर बेचने की उसकी मजबूरी भी, क्योंकि यहाँ से वापस ले जाए , तो लाने ले जाने चढ़ाने -उतारने का दोहरा भारी खर्च कैसे सहन करें !

इन सब बातों के अतिरिक्त कृषि आदानों की गुणवत्ता, उनकी बढ़ती लागत। वजन की कमी। समय पर उपलब्धता नहीं होना। समय के साथ- साथ किसान के अपने पारिवारिक खर्चों में बढ़ोत्तरी जैसे पहले बच्चों की पढ़ाई लगभग न्यूनतम खर्च में हो जाती थी। आज़ निजी स्कूलों में प्रतिमाह हजारों रुपए व्यय , उनके रहन-सहन , पहनावा, पुस्तकें आदि पर भी काफी खर्च। वहीं अन्य सामाजिक दायित्व , आवागमन समय की महत्ता के दृष्टिगत व्यय साध्य हो गए हैं। बैंक, आधार , फार्मर आई डी आदि में ओटीपी की अनिवार्यता के लिए मोबाइल डाटा, ई मेल, टीवी, कम्प्यूटर पर भी भारी खर्च किसान के आय व्यय चक्र को तेज़ी से घुमा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब किसान पहले की तुलना में बाजार की निर्भरता पर पहुंच गया है। केवल उत्पादन बढ़ाने से ही किसान लाभान्वित नहीं होने वाला अपितु हमें यह भी समझना होगा कि एक बीघा क्षेत्र में फसल उत्पादन करने में कुल खर्च कितना हो रहा है। इस फसल को बेचने के बाद लागत की तुलना में उसके पास कितना बचा ! इसके लिए किसान बर्षो से सी 2 लागत पर + 50 प्रतिशत मुनाफा (उत्पादन की कुल लागत जिसमें जमीन का किराया और पूंजी पर ब्याज भी शामिल हो) की मांग दोहराता रहा है।

हमारी सोच में किसानी लागत, फसल वार उत्पादकता, उस अनुसार उचित मूल्य जिसमें लाभकारी सुरक्षित आय स्पष्टतः परिलक्षित रहे तभी किसान व खेती के लहलहाने की उम्मीद जागेगी। तभी खेत किसान के पास सुरक्षित रहेंगे और उसका परिवार वास्तविक रूप से खुशहाल होगा। रोजगार मूलक कृषि के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी सदैव सुदृढ़ता पाती जाएगी।

बृज नेहरू पाटीदार
जनकपुर लेखक व पत्रकार
नीमच

मौसम का यू-टर्न और किसान की त्रासदी

देश में मौसम अब भरोसेमंद नहीं रहा। कभी लंबा सूखा, कभी अचानक मूसलाधार बारिश, कभी खेतों में दरारें, कभी पानी में डूबी फसलें। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसे अब अनदेखा करना देश के खाद्य-सुरक्षा तंत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों के साथ अन्याय होगा। इस समय उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और जनहानि की जो तस्वीर बनी है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मौसम का यू-टर्न अब आपदा में बदल चुका है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसान एक ही मौसम में दोहरी मार झेल रहा है। पहले बारिश की कमी से बोआई, सिंचाई और उत्पादन पर असर पड़ता है। फिर जब फसल पककर कटाई के करीब पहुंचती है, तब असमय भारी वर्षा, जलभराव और तेज हवाएं सालभर की मेहनत को मिट्टी में मिला देती हैं। यह केवल खेत के नुकसान की बात नहीं है। यह किसान की आय, उसके कर्ज, उसकी अगली फसल की तैयारी और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का संकट है।

आज स्थिति यह है कि खेती का जोखिम असाधारण रूप से बढ़ गया है। मौसम अब अनुमान के मुताबिक नहीं चल रहा। लंबे सूखे के बाद अचानक अत्यधिक वर्षा, और कई बार एक ही सीजन में बार-बार मौसम का बिगड़ना, खेती को अस्थिर बना रहा है। उत्तर भारत जैसे बड़े कृषि क्षेत्र में जब बारिश का कहर बरसता है, तो उसका असर सिर्फ खेत तक नहीं रहता। मंडियां प्रभावित होती हैं, सड़कें बंद होती हैं, परिवहन बाधित होता है, मजदूरी रुकती है और बाजार में अनाज तथा सब्जियों की आपूर्ति असंतुलित हो जाती है। यानी एक मौसमीय घटना पूरे आर्थिक चक्र को झकझोर देती है।

यह भी सच है कि इस संकट का दोष केवल प्रकृति पर डालकर बचा नहीं जा सकता। जलवायु परिवर्तन अब दूर की बहस नहीं रहा। यह हमारे खेत, गांव, जलस्रोत, फसल-चक्र और आम जीवन में प्रवेश कर चुका है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, बादल फटने जैसी घटनाएं और चरम मौसम की परिस्थितियां बढ़ रही हैं। अगर नीति-निर्माता अभी भी इसे सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव समझ रहे हैं, तो यह गंभीर भूल होगी। अब मौसम विभाग की चेतावनियों को सिर्फ समाचार नहीं, नीति-निर्देश की तरह लेना होगा।सरकारें हर आपदा के बाद राहत पैकेज की घोषणा करती हैं। कुछ जगहों पर गिरदावरी होती है, कुछ जिलों में सर्वे होते हैं, कुछ किसानों के खातों में सहायता पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब नुकसान की वास्तविक भरपाई कर पाता है? सच्चाई यह है कि अधिकांश किसान को राहत समय पर नहीं मिलती। जब तक मुआवजा आता है, तब तक वह अगली बोआई के लिए उधार ले चुका होता है। कई बार बीमा दावों में देरी होती है, कागजी औपचारिकताएं लंबी खिंचती हैं और किसान प्रशासनिक चक्र में फंस जाता है। एक संवेदनशील राज्य व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती।आज जरूरत है केवल राहत की नहीं, बल्कि संरचनात्मक तैयारी की। सबसे पहले खेत स्तर पर जलनिकासी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है, वहां सिर्फ क्षतिपूर्ति नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। नालों की सफाई, ड्रेनेज नेटवर्क का सुधार, खेतों के आसपास जलनिकासी की व्यवस्था और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग अनिवार्य है। गांवों की जमीन, तालाबों, नालों और प्राकृतिक प्रवाह-पथों पर अतिक्रमण भी इस संकट को बढ़ाता है। इस पर सख्ती जरूरी है।दूसरी जरूरत है फसल-योजना में बदलाव की। बदलते मौसम को देखते हुए वही पुरानी कृषि रणनीति अब काम नहीं करेगी। फसल किस्मों, बोआई के समय, सिंचाई पद्धति और जोखिम-प्रबंधन को जलवायु के अनुरूप ढालना होगा। ऐसे बीज विकसित और प्रोत्साहित किए जाने चाहिए जो सूखा और अत्यधिक वर्षा, दोनों स्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर टिक सकें। कृषि विज्ञान केंद्रों और विस्तार सेवाओं को गांव-गांव सक्रिय करना होगा, ताकि किसान को मौसम के अनुसार त्वरित सलाह मिल सके।तीसरा बड़ा प्रश्न बीमा और मुआवजा प्रणाली का है। फसल बीमा योजना का लाभ तभी है जब वह वास्तव में समय पर और पारदर्शी हो। आज किसान को सबसे अधिक शिकायत इसी बात की रहती है कि नुकसान वास्तविक होता है, लेकिन मुआवजा औपचारिकताओं में उलझ जाता है। डिजिटल सर्वे, उपग्रह आधारित आकलन और स्थानीय सत्यापन को जोड़कर ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें नुकसान का आकलन जल्दी हो और भुगतान सीधे किसानों तक पहुंचे। राहत व्यवस्था में देरी, दरअसल, दूसरी आपदा है।इस पूरे संकट का एक सामाजिक आयाम भी है। किसान सिर्फ उत्पादन का नाम नहीं है, वह गांव की रीढ़ है। जब उसकी फसल बर्बाद होती है, तो उसका परिवार केवल आर्थिक नहीं, मानसिक तनाव भी झेलता है। कर्ज, अनिश्चितता और असुरक्षा आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं। कई छोटे और सीमांत किसान तो एक खराब मौसम के बाद संभल ही नहीं पाते। यही वह जगह है जहां राज्य की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सरकार का काम केवल नुकसान गिनना नहीं, बल्कि किसान को फिर से खड़ा करना है।उत्तर भारत में हाल की बारिश ने यह भी दिखाया है कि शहर और गांव, दोनों जलनिकासी की बदहाली से जूझ रहे हैं। जहां थोड़ी सी बारिश में सड़कें डूब जाती हैं, वहां खेतों का बचना मुश्किल है। शहरी अव्यवस्था और ग्रामीण उपेक्षा एक ही समस्या के दो रूप हैं। अगर हम बुनियादी ढांचे को जलवायु-संवेदनशील नहीं बनाएंगे, तो हर साल यही दृश्य दोहराया जाएगा। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी फसल बर्बादी, कभी महंगाई।अब समय आ गया है कि देश कृषि नीति को मौसम-केन्द्रित नहीं, जलवायु-केन्द्रित बनाए। यह केवल कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें जल संसाधन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास और राज्य प्रशासन सभी की संयुक्त भूमिका है। नीतियों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि किसान को मौसम की मार से न्यूनतम नुकसान हो। इसके लिए पूर्व चेतावनी, त्वरित राहत, वैज्ञानिक खेती, स्थानीय जल प्रबंधन और मजबूत बीमा तंत्र–इन सबको एक साथ काम करना होगा।कड़वी सच्चाई यह है कि अगर हम अभी नहीं चेते, तो यह संकट और गहरा होगा। खाद्य उत्पादन पर असर पड़ेगा, ग्रामीण कर्ज बढ़ेगा, किसानों का पलायन तेज होगा और कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए यह केवल किसान का सवाल नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सवाल है। जिस देश की खेती मौसम के भरोसे छोड़ दी जाए, वह देश दीर्घकालिक संकट से नहीं बच सकता।सरकार को अब घोषणाओं की भाषा से बाहर निकलकर कार्रवाई की भाषा में आना होगा। समय पर सर्वे, पारदर्शी मुआवजा, मजबूत ड्रेनेज, जलवायु-संवेदनशील कृषि योजना और किसानों को तुरंत राहत देने की व्यवस्था, यही असली जवाब है। मौसम का यू-टर्न अब साधारण मौसमी घटना नहीं, खेती और भविष्य दोनों के लिए संकट-घंटी है। इसे सुनना और समझना ही नहीं, अब उस पर तत्काल काम करना भी जरूरी है।

एडवोकेट, जयदेव राठी

फ्यूजन सीएक्स का 702 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 अक्टूबर को खुलेगा, 275-289 रुपये प्रति शेयर होगा प्राइस बैंड

ग्राहक अनुभव सेवाओं और एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली फ्यूजन सीएक्स लिमिटेड ने अपने 702 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 275 से 289 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। आईपीओ बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को खुलेगा और शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को खुलेगी।

कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी का आईपीओ दो हिस्सों में होगा। इसमें 500 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 202 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री प्रवर्तक शेयरधारकों पीएनएस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और राशिश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत की जाएगी।

कंपनी नए शेयरों से प्राप्त शुद्ध राशि में से 275 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने और कुछ सहायक कंपनियों के बकाया कर्ज के भुगतान या समय से पहले चुकाने में करेगी। वहीं, 61 करोड़ रुपये अपनी अधीनस्थ सहायक कंपनियों ओमाइंड टेक्नोलॉजीज इंक. और ओमाइंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए रखे जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल आईटी टूल्स आर्या और माइंडवॉइस को उन्नत बनाने में किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग संभावित अधिग्रहणों के जरिये कारोबार के विस्तार और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2004 में पंकज धनुका और किशोर सराओगी ने फ्यूजन सीएक्स की स्थापना की थी। कंपनी अपने क्षेत्र के गहरे अनुभव और स्वामित्व वाले एआई टूल्स के जरिये ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देती है। इसकी सेवाओं में जनरेटिव एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राहक जुड़ाव, परिचालन दक्षता और डिजिटल बदलाव को बढ़ावा मिलता है। कंपनी कई भाषाओं और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर ग्राहकों से संपर्क की सुविधा भी देती है।

कंपनी दूरसंचार एवं यूटिलिटी, स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान, हाई-टेक और यात्रा (एचटीटी), बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई) तथा खुदरा कारोबार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अरबी, मंदारिन, इतालवी और हिंदी सहित 28 भाषाओं में सहायता सेवाएं प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में फ्यूजन सीएक्स ने परिचालन से 1,818 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 169 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया। 30 जून 2026 तक कंपनी में 13,735 कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी 13 देशों में कारोबार करती है और इसके 40 रणनीतिक रूप से स्थित डिलीवरी सेंटर हैं, जो अलग-अलग समय क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

कंपनी के 208 ग्राहकों के पोर्टफोलियो में फॉर्च्यून 1000 की 22 कंपनियां शामिल हैं। इसके प्रमुख ग्राहकों में डीएमईसी कैपिटल सर्विसेज, पार्क वेस्ट, टेलाइड, अचीव कलेक्शन, अमेरिफ्लेक्स, कोस्टलाइन, अजियो, मीशो, कॉल कोर मीडिया, अरविंद फैशन, प्रोपन्यू एसए, लियोनार्डो होटल्स, इंश्योरेंस एक्सप्रेस, के2 क्लेम्स सर्विसेज, सेंट्री क्रेडिट और ट्राया शामिल हैं।